Labour Commissioner of Delhi Administration in 1986 to verify the membership of the Trade Union functioning in that Corporation for granting the recognition;

(b) if so, whether Labour Commissioner has submitted his report in this regard;

(c) if so, the date of submission of report and what action has been taken by the management; and

(d) what are the details of the recommendations made by the Labour Commissioner and the action Government propose to take on these recommendations and by when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to information received from the Delhi Administration, the Labour Commissioner submitted his report on 28-10-1987 recommending the Delhi State Civil Supplies Corporation Employees Union for recognition. The matter has been placed before the Board of Directors of the Delhi State Civil Supplies Corporation for a decision.

विज्ञापनों के माध्यम से दूरदर्शन की आय

2791. श्रीमती वीणा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन की आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1987 88 के दौरान दूरदर्शन विज्ञापनों से केवल 37 करोड रुपये की आय प्राप्त कर सका है; यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नई विज्ञापन नीति के अन्तर्गत विज्ञापनदाताओं को 15 से 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और क्या नई विज्ञापन नीति उद्भोक्तावाद को बढ़ावा दे रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। दूरदर्शन की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों से प्राप्त राजस्व है। विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों से दूरदर्शन द्वारा अर्जित किया गया कुल राजस्व वित्तीय वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमश: 60.2 करोड रुपये, 98 करोड़ रुपए तथा 136.3 करोड़ रुपए था।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1987-88 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित किया गया कुल राजस्व 136.3 करोड़ रुपए था।

(ग) विज्ञापन समय, जो सामान्यत: उपयोग में नहीं आता, का उपयोग करने हेतु विज्ञापनदाताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वर्तमान दर कार्ड, पैकेज के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक छूट प्रदान करता है अर्थात् उस श्रेणी के कार्यक्रमों के साथ विज्ञापनों की अधिक संख्या में बुकिंग करना जो अन्य किसी प्रकार से विज्ञापनों को आकर्षित नहीं करते। इस सुझाव का यह प्रमाण है कि यह छूट उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है।

प्रचार माध्यम अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण

2792. श्री कपिल वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रचार माध्यम अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके अनसार स्कूल जाने वाले 90 प्रतिशत बच्चे टेलीविजन के आदी हो

गये हैं; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे शैक्षिक और सूचनात्मक कार्यक्रमों की बजाये बच्चे चित्रहार, फीचर फिल्म, एनीमेशन फिल्म और धारावाहिकों जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों को देखना अधिक पसंद करते हैं, यदि हां, तो दूरदर्शन सूचनात्मक और शैक्षिक संबंधी अपने लक्ष्य को पूरा करने में कहां तक सफल रहा है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा चित्रहार, फीचर फिल्म, प्रादेशिक फीचर फिल्म, धारावाहिक एनीमेशन फिल्म और खेल जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए कितने-कितने समय का आवंटन किया जाता है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल०भगत) : (क) और (ख) इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आयी हैं। दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान यूनिट तथा बाहरी अभिकरणों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बच्चे फन्तासी, एक्शन और कहानी के तत्व वाले कार्यक्रमों को पसंद करते है। दूरदर्शन का बच्चों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम टेलीकास्ट करने का प्रयास रहा है जो मनोरंजक होने के अलावा शैक्षिक और सूचनापरक होते हैं। तथापि बच्चों को यथोचित बोध कराने के लिए मूलतः शैक्षिक और सूचनापरक कार्यक्रमों को मनोरंजन के साथ जोड़ दिया जाता है।

(ग) मनोरंजक, शैक्षिक और सूचनापरक कार्यक्रमों का सीमांकन करना कठिन है क्योंकि दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट कार्यक्रमों में ये अवयव मिले-जुले होते हैं।

Suspension of the Executive Director of Aonla Project

2793. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Board of Directors of IFFCO has passed a resolution last month suspending the Executive Director of Aonla Project; if so, on what charges; and

(b) whether the Department of Fertilizers has communicated to IFFCO that the resolution would have no effect whatsoever and has asked for reconciliation and review the suspension decision if so, the reasons that the Department has passed the order; what action has been taken in this regard by the IFFCO?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Yes, Sir. Board of Directors of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) in its meeting held on 7th February, 1989 passed a resolution to suspend the Executive Director (Aonla) for alleged overpayments to 2 transport contractors.

(b) Yes, Sir. Government of India *vide* its order dated 9th February, 1989 declared that the resolution to suspend the Executive Director (Aonla) shall be of no effect whatsoever and further directed that IFFCO shall review and reconsider the matter by following the prescribed procedure in keeping with the principles of natural justice. The above order is being implemented by IFFCO.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2794. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री अबरार अहमद खान :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे आटा, चीनी, चावल, दूध, वनस्पति घी, खाद्य तेल, कपड़ा, ईंधन इत्यादि के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) विशेषत: 1986, 1987 और 1988 के वर्षों में अक्तूबर-नवम्बर के महीनों में इन वस्तुओं का वर्षवार मूल्य क्या रहा है;

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को दीर्घावधि आधार पर स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और